

मध्य प्रदेश ट्रांसको का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सहि तोमर ने बताया कि जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू बैंक द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट का अंतिम कार्य मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पूरा कर लिया है। इसमें 400 के.वी. आष्टा-उज्जैन डबल सर्कट लाइन ऊर्जीकृत की गई।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि पूरे देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बज्रिली के सहज ट्रांसमिशन के लिये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिये कुछ राज्यों में से मध्य प्रदेश को भी चुना गया था।
- कुल प्रोजेक्ट 2100 करोड़ रुपए में से 840 करोड़ रुपए का लोन जर्मनी के बैंक के.एफ.डब्ल्यू ने स्वीकृत किया था। इन कार्यों को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरा कर लिया है।
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर एम.एम. ढोके ने बताया कि इस स्कीम में प्रदेश में 400 के.वी. के तीन सब-स्टेशन, 220 के.वी. के सात सब-स्टेशन, 400 के.वी. की 5 डबल सर्कट लाइनें, 220 के.वी. की 15 डबल सर्कट लाइनें तथा 132 के.वी. की 26 डबल सर्कट की कुल 2773 सर्कटि कमी. अर्थात् उच्च दाब लाइनें निर्मित की गईं।
- इस स्कीम से 400 के.वी. की 1890 एम.वी.ए. क्षमता, 220 के.वी. में 2400 एम.वी.ए. क्षमता तथा 132 के.वी. में 498 एम.वी.ए. कुल 4788 एम.वी.ए. अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ट्रांसमिशन में नेटवर्क में जोड़ी गई।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सागर, उज्जैन तथा मंदसौर में 400 के.वी. के सब-स्टेशन, सेंधवा, कानवन, जावरा, सैलाना, गुडगाँव, रतनगढ़ तथा नलखेड़ा में 220 के.वी. के सब-स्टेशन तथा 132 के.वी. के दो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किये हैं।